

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -22/2012/सिरोही

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-सिरोहीअपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स सिरोही ट्रेक्टर सर्विस, सिरोहीप्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी. ओझा

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित

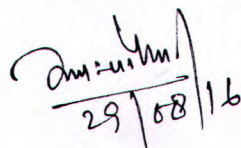
(एकपक्षीय कार्यवाही)

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 29.08.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-सिरोही (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 105/आरवैट/सिरोही/2010-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.06.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 82 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर से नियमानुसार वेट अदा कर खरीद तथा वेट वसूल कर रिटेल बिक्री करता है। प्रत्यर्थी मासिक करदाता नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.08.2009 द्वारा प्रत्यर्थी पर इस अधिनियम की धारा 58 के तहत 16,188/-रूपये की शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी करदाता द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसे दिनांक 16.06.2011 को आंशिक रूप से स्वीकार कर धारा 58 के पुराने प्रावधान के अनुसार प्रत्येक विवरणी को विलम्ब से पेश करने पर 500/-रूपये के हिसाब से शास्ति आरोपित करते हुए प्रत्येक प्रकरण में कुल 2000/- की शास्ति यथावत रखी तथा शेष रूपये 14,188/- की शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 16.06.2011 से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।


29/08/16

लगातार.....2

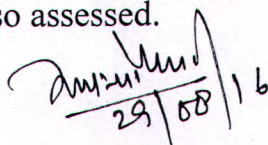
3. विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में धारा 58 के तहत दिनांक 08.07.2009 के वित्त अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन के अनुक्रम में शास्ति आरोपित की गई है। यह प्रकरण वर्ष 2007-08 से संबंधित है तथा कर निर्धारण आदेश उक्त संशोधन के बाद पारित किया गया। अतः शास्ति का आरोपण कर निर्धारण आदेश पारित करने के समय विद्यमान विधिक प्रावधानों के अनुकूल ही किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत मायारानी पुंज बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दिल्ली के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को दोहराया जिसके अनुसार विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (continuing offence) की श्रेणी में आता है। जो विलम्ब (default) होने के साथ यह अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने तक जारी रहता है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने आगे कहा है कि माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी निर्णित किया है कि अवहेलना (Default) के समय जो कानून प्रचलित या उसके प्रावधान के अनुसार शास्ति आरोपणीय है। इस प्रकार उप राजकीय अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा यह अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 58 के तहत नये एवं पुराने प्रावधानों के तहत रुपये 16,188/- की शास्ति जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित की गयी है, वह तथ्यों से परे, अविधिक एवं अव्यवहारिक है। वेट अधिनियम की धारा 58 के अनुसार दिनांक 08.07.2009 के संशोधन से पूर्व मासिकदाता पर रुपये 10/- प्रतिदिन या कर दायित्व का 20 प्रतिशत तक अधिकतम शास्ति व कर दायित्व रुपये 20,000/- रुपये वार्षिक के कम रहने पर अधिकतम शास्ति रुपये 500/- आरोपित करने का प्रावधान था। दिनांक 08.07.2009 को संशोधन के पश्चात् प्रथम 15 दिन तक 100/- रुपये प्रतिदिन व तत्पश्चात् प्रतिदिन रुपये 500/- व अधिकतम कर दायित्व का 30 प्रतिशत तक शास्ति का प्रावधान है। अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि जो रिटर्न 8 जुलाई, 2009 के बाद देय बनते हैं, उसी पर दिनांक 08.07.2019 के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रुपये 500/- ही आरोपित की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.06.2011 का समर्थन करते हुए यह

Amal Kumar
29/08/16

लगातार.....3

कथन किया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने उक्त आदेश में धारा 58 के पुराने प्रावधान के अनुसार प्रत्येक विवरणियों विलम्ब से पेश करने पर 500/-रूपये के हिसाब से शास्ति आरोपित करते हुए प्रत्येक प्रकरण में कुल 2000/- की शास्ति यथावत रखी तथा शेष रूपये 14,188/- की शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा वर्तमान अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व रिकॉर्ड का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किया गया है। जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत 16,188/-रूपये शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 16.06.2011 द्वारा उक्त आरोपित शास्ति में से 14,188/- रूपये इस आधार पर अपास्त किया कि "अपीलार्थी मासिक करदाता नहीं है तथा उक्त प्रकरण वर्ष 2007-08 से संबंधित है। नये प्रावधान दिनांक 08.07.2009 से ही प्रभावी हुए हैं तथा इन्हें पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं दिया गया है। अतः संशोधन दिनांक 08.07.2009 उन्हीं विवरणियों के मामलों में प्रभावी होंगे जो कि दिनांक 08.07.2009 के पश्चात् दाखिल किये जाने हैं। अतः बिक्री विवरण पत्रों का विलम्ब दिनांक 08.07.2009 से पूर्व प्रारम्भ हो गया था तथा आलोच्य अवधि भी दिनांक 08.07.2009 से पूर्व की है। इसलिये धारा 58 के संशोधित प्रावधान जो कि दिनांक 08.07.2009 से प्रभावी हुए हैं के तहत इन प्रकरणों में शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है।"
6. वार्षिक विवरण पत्र 10ए विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए धारा 58 के अन्तर्गत दिनांक 07.07.2009 तक 10/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से तथा दिनांक 08.07.2009 से नये संशोधित प्रावधानुसार 15 दिन के विलम्ब तक 100/- रूपये प्रतिदिन एवं इसके आगे के विलम्ब के लिये प्रतिदिन 500/-रूपये अथवा अधिकतम आउटपुट का 30 प्रतिशत के हिसाब से शास्ति आरोपित की गई। दिनांक 08.07.2009 से पूर्व यानि दिनांक 07.07.2009 तक वैट अधिनियम की धारा 58 के जो प्रावधान प्रभावी थे, वो इस प्रकार हैं:-
- (i) In case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees ten per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in aggregate twenty percent of the tax so assessed.


29/08/16

लगातार.....4

- (ii) In all other cases, a sum equal to rupees five per day subject to a maximum limit of rupees five hundred, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

चूंकि हस्तगत प्रकरण में वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति विवादित है अतः वैट अधिनियम की धारा 58 का अध्ययन करना सुसंगत है। दिनांक 08.07.2009 से पुनः स्थापित (substitute) की गई है, वो इस प्रकार है :-

"58 Penalty for failure to furnish return - Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorized by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed "to furnish" prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty.(i) in case the dealer is required "to pay tax monthly under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed; and

- (iii) in all other cases, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

7. हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्डपीठ तीन सदस्यीय माया रानी पुंज बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देहली के प्रकरण में दिए गए निर्णय (65 एसटीसी 416) में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख किया जाना समीचीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि यद्यपि विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने का अपराध 29 सितम्बर, 1961 से प्रारम्भ हुआ और यह अपराध तब तक जारी रहेगा। जब तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। इस प्रकार विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (Continuing Offence) की श्रेणी में आता है। जो विलम्ब (Default) होने के साथ अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने तक जारी रहता है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

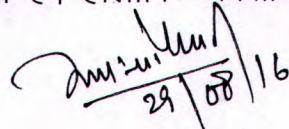
"The imposition of penalty not confined to the first default but with reference to the continued default is obviously on the footing that non-compliance with the obligation of making a return, is an infraction as long as the default continued. Without sanction of law, no penalty is imposable with reference to the defaulting conduct. The position that penalty is imposable not only for the first default but as, long as the default continues and such penalty is to be calculated at a prescribed rate on monthly basis is indicative of the legislative intention in unmistakable terms that as long as the assessed does not comply with the requirements of law, he continues to be guilty of the infraction and exposes himself to the penalty provided by law."

Amr-21/11/16
29/08/16

लगातार.....5

उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण था कि व्यवहारी, जिसको कर निर्धारण वर्ष 1961-62 के लिए आयकर विवरणी दिनांक 28.09.1961 तक प्रस्तुत करनी थी, ने उक्त अवधि में विवरणी प्रस्तुत नहीं कर, लगभग सात माह विलम्ब से यानी 03.05.1962 को प्रस्तुत की। परन्तु उक्त अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1922 के स्थान पर आयकर अधिनियम, 1961 (1 अप्रैल 1862 से) प्रभावी हो चुका था, अतः आयकर अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27(1)(ए) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विलम्ब से प्रस्तुत विवरणी पर शास्ति आरोपित कर दी। माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27(1)(ए) के अन्तर्गत शास्ति इस धारा के प्रावधानुसार आरोपित की जानी न्यायोचित है क्योंकि इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् भी यह अपराध जारी रहा।

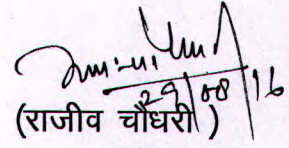
9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने का अपराध तब तक जारी रहेगा, जब तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। इस प्रकार यह निरन्तर अपराध (continuous offence) की श्रेणी में आता है। जो विक्रय विवरणियां प्रस्तुत करने तक जारी रहता है।
10. राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2359, 2360 व 2361/2011/सिरोही के मामले में दिनांक 29.08.2012 को दिये गये निर्णय में भी अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति की विधिसम्मत माना गया है।
11. यहां यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2007-08 की चार त्रैमास का विवरणियों पर कर विवरणिका विलम्ब से जमा कराये जाने पर धारा 58 के अधीन कुल 7,770/-रूपये शास्ति अधिरोपित की। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी। अपने अपील मीमों में व्यवसायी ने धारा 58 के तहत शास्ति के 7,770/-रूपये व मासिक कर दायित्व के आधार पर देय कर का मासिक दर पर कुल ब्याज 8,418/-रूपये को भी इस आधार पर चुनौती दी कि व्यवसायी का कर दायित्व त्रैमासिक होने पर कुल देय कर पर ब्याज 623/-रूपये बनता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.06.2011 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत 16,188/-रूपये शास्ति अधिरोपित किये जाने को विधिसम्मत नहीं माना है। हालांकि व्यवसायी को मासिक करदाता नहीं माना


29/08/16

लगातार.....6

गया है, किन्तु ब्याज की राशि रूपये 8,418/- के आरोपण के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया है। केवल धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में विवेचन किया गया है। अतः उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा ब्याज के आरोपण के संबंध में विवेचन नहीं किये जाने से यहीं निष्कर्ष निकलता है कि सम्पूर्ण राशि 16,188/- रूपये जिसमें ब्याज भी सम्मिलित था। उसे धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण मान कर प्रकरण का निस्तारण किया गया है, जो कि एक तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि है।

12. परिणामतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.211 को अपास्त किया जाता है एवं उक्त प्रकरण को ब्याज की राशि के संबंध में निर्णय पारित करने हेतु तथा धारा 58 के तहत अधिरोपित शास्ति को मायारानी पुंज बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दिल्ली व इस बोर्ड के निर्णयों के प्रकाश में नए सिरे से निस्तारित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।
13. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य